

यूपी में बनेगा देश का पहला डाटा कारिडोर

छह लाख करोड़ रुपये की लागत से छह गीगावाट क्षमता के डाटा क्लस्टर होंगे स्थापित

हेमंत श्रीवास्तव • जागरण

लखनऊ : प्रदेश सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए देश का पहला डाटा कारिडोर विकसित करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पहले चरण में करीब छह लाख करोड़ रुपये के निवेश से छह गीगावाट क्षमता के डाटा क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। परियोजना का रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (बीसीजी) को सौंपी गई है, जो छह माह में अपनी रिपोर्ट देगी।

डाटा कारिडोर को विकसित कराने की जिम्मेदारी राज्य परिवर्तन आयोग को दी गई है। आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि डाटा कारिडोर विकसित करने से पहले बीसीजी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी, पानी और बिजली की उपलब्धता का विस्तृत अध्ययन करेगी। डाटा सेंटर के संचालन के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली और



मनोज कुमार सिंह (फाइल)

● अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप छह माह में तैयार करेगी विस्तृत रोडमैप

पर्याप्त पानी आवश्यक होता है, इसलिए उपयुक्त स्थान का चयन सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। एक गीगावाट क्षमता का डाटा सेंटर स्थापित करने पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी।

वर्तमान में दुनिया में लगभग 120 गीगावाट क्षमता के डाटा सेंटर हैं। इनमें अमेरिका 50 गीगावाट, चीन 25 गीगावाट और यूरोप 14 गीगावाट क्षमता के साथ अग्रणी हैं। भारत में अभी 1.7 गीगावाट क्षमता के डाटा सेंटर संचालित हैं, जबकि 1.8 गीगावाट क्षमता के नए

डाटा सेंटर के लिए पहले मिट्टी, पानी व बिजली की होती है जांच

डाटा सेंटर स्थापित करने से पहले भूमि की भार वहन क्षमता का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विशेषज्ञ 10 से 15 मीटर गहराई तक मिट्टी के नमूने लेकर यह जांचते हैं कि जमीन भवन, सर्वर रैंक और अन्य भारी उपकरणों का भार सुरक्षित रूप से उठा सकती है या नहीं। साथ ही भूजल स्तर, भविष्य में भवन के धंसने की आशंका और भूकंप जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़े जोखिमों का भी आकलन किया जाता है।

डाटा सेंटर में बड़ी संख्या में सर्वर, कूलिंग सिस्टम और बिजली से संचालित उपकरण लगे होते हैं। इसलिए मजबूत भूमि का चयन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

डाटा सेंटर निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 350 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर हैं और चार नए डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। देश की कुल डाटा मांग में



एक मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर को संचालित करने के लिए लगभग एक मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा सर्वर, सीपीयू और अन्य नेटवर्किंग उपकरणों से निकलने वाली गर्मी को नियंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में पानी की भी जरूरत पड़ती है। इसी कारण डाटा सेंटर के लिए ऐसी जगह का चयन किया जाता है, जहां पर्याप्त बिजली, पानी और सुरक्षित भूगर्भीय परिस्थितियां उपलब्ध हों।

उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत मानी जाती है, जिससे यह परियोजना राज्य को डाटा हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।